DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 20 मई 2022

'बीजेपी नेताओं के अतिक्रमण पर बुलडोजर कब'

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जारी की लिस्ट

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने अतिक्रमण को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा करते हुए एक सूची जारी की है और आरोप लगाया है कि दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी, छैल बिहारी गोस्वामी, राजा इकबाल सिंह, मुकेश सूर्यान, अनिल जैन, मीनाक्षी लेखी, मनजिंदर सिंह सिरसा सहित दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अतिक्रमण कर रखा है। बीजेपी शासित एमसीडी इन नेताओं के अतिक्रमण पर बुलडोजर कब चलाएगी?

केंद्रीय मंत्री से लेकर पार्षदों तक पर अतिक्रमण करने के आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लिस्ट में सबसे पहला नाम ईस्ट एमसीडी के नेता बिपिन बिहारी का है। उन्होंने सरकारी जमीन पर सीढ़ियां बनाकर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा

सौरभ भारद्वाज ने किए कड़े प्रहार

मयूर विहार फेस-1 में इन्होंने दो मकानों जोड़ रखा है, जो कि गैर-कानूनी है। अगला नाम ईस्ट एमसीडी के पूर्व मेयर निर्मल जैन का है। इन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। विधायक ओम ने सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाकर अपने लिए पार्किंग बना रखी है। अगला नाम नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता का है। इन्होंने अपने घर के आगे सरकारी जमीन पर कब्जा कर करीब 7 फुट का रैम्प बना रखा है और एक बगीचा बना रखा है। नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह के घर की सीढ़ियां गैर-कानूनी हैं। नॉर्थ एमसीडी की पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल ने सरकारी जमीन पर बहुत बड़ा गार्डन बनाया है।

उन्होंने कहा कि इसमें रमेश बिधूड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा है। रमेश बिधूड़ी के भतीजे विक्रम बिधूड़ी ने भी अतिक्रमण किया है। मीनाक्षी लेखी का चितरंजन पार्क के सामने शिवालिक अपार्टमेंट में दफ्तर है। यहां पर इन्होंने एमसीडी के पार्क पर कब्जा करके अपना दफ्तर बना रखा है। राज्यसभा सांसद अनिल जैन सैनिक फार्म में अनुपम गार्डन में रहते हैं, जहां निर्माण तक की इजाजत नहीं है। पूर्व विधायक विजय जॉली भी यहीं रहते हैं, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है। एनडीएमसी के लीडर ऑफ हाउस छैल बिहारी गोस्वामी ने डीडीए फ्लैट को बढ़ाकर पूरी कोठी बना रखी है।

सौरभ ने कहा कि साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने कॉलोनी के बेसमेंट में अवैध निर्माण करवाकर घर बना रखा है। आशीष सूद ने सरकारी जमीन पर गार्डन बना रखा है। अगला मकान बीजेपी के बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का है। इन्होंने गैर-कानूनी तरीके से रैम्प और कोठी के बाहर गार्ड का कमरा बना रखा है। बीजेपी बताए कि वह उपरोक्त 16 नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलाएगी?

बीजेपी का जवाबः बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि यह अजीब विडम्बना है कि सौरभ भारद्वाज जिस दफ्तर में बैठकर बीजेपी नेताओं पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें आम आदमी उस दफ्तर के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध कमरे और खोखे नजर नहीं आते। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आप नेताओं ने आज बीजेपी के कुछ नेताओं के घरों के बाहर बने रैंप और नाम पट्टी को अतिक्रमण बताकर राजनीतिक ओछेपन की हर हद पार कर दी है।

हिन्दुस्तान

डीडीए ने अतिक्रमण अभियान बंद रखा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं चलाया जा सका।

डीडीए की ओर से गुरुवार को पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी समेत कई इलाकों में अभियान चलाया जाना था। इस अभियान के लिए पुलिस बल नहीं मिलने के कारण डीडीए की ओर से अभियान को स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में ओखला समेत यमुना के नजदीकी इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 20 मई, 2022

पौधारोपण के लिए न भूमि है, न सरकार को देंगे : डीडीए

डीडीए ने केंद्रीय पर्यावरण सचिव को बताई स्थिति

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

> मौजूदा स्थिति में एक के बदले 10 पौधे लगाने की नीति अप्रासंगिक हो गई है। जब यह नीति बनाई गई थी, तभी दिल्ली का हरित क्षेत्र बहुत कम था जबकि अब काफी हो चुका है। इसलिए इसे भी बदला जाना चाहिए। हरित क्षेत्र के साथ दिल्ली की विभिन्न बुनियादी जरूरतें और विकास परियोजनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।-राजीव कुमार तिवारी, प्रधान आयुक्त (उद्यान), डीडीए

प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली सरकार को जमीन उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर दिए हैं। डीडीए का कहना है कि जब उसके पास जमीन है ही नहीं तो देने का सवाल भी नहीं उठता। मुख्य सचिव को दो बार पत्र लिखने के बाद डीडीए ने अब केंद्रीय पर्यावरण सचिव को भी पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिल्ली के संदर्भ में द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के दिशा निर्देशों में बदलाव करने भी आग्रह किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अब अगर पौधारोपण के लिए और जमीन दी जाएगी तो फिर दिल्ली से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की सचिव लीना नंदन को पत्र लिखकर कहा गया है कि जमीन की कमी होने से द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना मुश्किल है। जमीन के जो छोटे-छोटे टुकड़े बचे हैं, वे राजधानी के विकास व इसकी अन्य जरूरतों के लिए हैं। मास्टर प्लान के तहत जो 15 प्रतिशत क्षेत्र इस उद्देश्य के निमित्त रखा गया है, वह भी 20 प्रतिशत तक पौधारोपण से भर चुका है। बताया गया है कि 1990 के बाद से दिल्ली में कोई भू अधिग्रहण नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि द स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट के नए संस्करण के अनुसार दिल्ली का हरित क्षेत्र अब 23 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसीलिए 42 साल पहले बनाए गए द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नियमों में बदलाव जरूरी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली राज्य नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र है। लिहाजा, प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली को अन्य राज्यों में भी जगह दी जा सकती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI *
FRIDAY, MAY 20, 2022

TIMES CITY

How tree-felling ban may hit many infra projects in capital

DMRC, NCRTC, DDA, PWD Among Agencies To Be Affected, To Scan Order

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The interim ban imposed by Delhi High Court on tree felling may have huge repercussions. Senior Delhi officials accept that if it continues for long, several infrastructure development projects being taken up by agencies such as Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), Public Works Department, New Delhi Municipal Council, NCRTC and Delhi Development Authority will be impacted.

According to forest department officials, both land-owning agencies as well as private individuals seek permission for felling trees for infrastructure projects and building or renovating houses. According to Delhi Preservation of Trees Act, 1994, compensatory plantation of 10 saplings has to be done for every tree felled.

Though Delhi government in December 2020 notified a tree transplantation policy, which said a minimum of 80% trees affected by a project must be transplanted and 80% of them must survive, the exact survival rate has always been questionable. "The basis of the court order seems based on the same. It has to be seen that the tree cover must increase," said an official.

While development agencies said they would closely study the order, officials confirmed the pace of development work would definitely slow down. "This decision will definitely impact our projects. In Delhi, there is not much vacant land available. Construction of all major flyovers, roads and underpasses will require tree felling," said a senior PWD official.

PWD engineer-in-chief Anant Kumar, however, said that construction of projects were in the final stages and had cleared all legal formalities. Earlier, the forest department had issued a restraining order in a streetscaping project on east Delhi's Vikas Marg and Narwana Road. "These individual cases are being worked out separately," added Kumar.

Construction work on Delhi Metro's Phase-IV expansion kickstarted just a few months before the Covid-19 outbreak, which resulted in huge delays in 2020 and 2021. The two other reasons for delay were land acquisition and permission to cut trees.

In fact, the first corridor from where the construction of Phase-IV began — Janakpuri West-RK Ashram Marg — saw work coming to a complete halt in August 2020 when DMRC received several notices from the forest and wildlife department over carrying out construction in deemed forest areas in the Janakpuri to Peeragarhi stretch.

DMRC shifted its focus on the much smaller Maujpur to Majlis Park corridor with the aim of commissioning it, even if partially, by 2022. However, the process of getting permission to fell trees at some locations took time. Now, the first section is expected to open in 2023.

Last month, DMRC received permission to fell 977 trees and transplant 1,963 in north forest division and 450 in south forest division (for Tughlaqabad-Aerocity corridor), but the stay could result in the agency not being able to remove the trees till further directions.

Out of the 82km Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System corridor, currently the focus is on completing the 17km Duhari-Sahibabad section in UP. The length of the corridor in Delhi is 14km and out of the total 25 stations, four are in Delhi. However, sources said the stay on tree felling may impact the pace of work in Delhi.

NDMC vice-chairperson Satish Upadhyay said the court direction would be implemented fully. "We have been emphasising on transplantation of trees rather than felling them. We are adopting proper procedure/technology to relocate trees to new sites. We have sought permission for transplantation of trees for three projects, including the bus terminal at Shivaji Stadium and development of Lodhi Road School of Excellence," he added.

HITTING A ROADBLOCK

Infrastructure projects likely to be affected by HC order

PWD
- Streetscaping on 16 roads
- Six-lane flyover between Punjabi Bagh and Raja Garden
- Elevated corridor between Anand Vihar and Apsara border
- Redevelopment of three main roads of central and New Delhi
- Three new flyovers at Nangloi, Hanuman Setu and Mayapuri

Delhi Metro
Three approved corridors of DMRC's Phase-IV expansion

Majlis Park-Maujpur **12.3km**

Janakpuri West-RK Ashram Marg **29.3km**

Aerocity-Tughlaqabad **23.6km**

Picture for representation

RRTS
14km of the total 82km-long Delhi-Meerut RRTS corridor that falls in Delhi

4 Number of stations out of total 25 in in the corridor that would come up in Delhi

NDMC
- School of Excellence, Lodhi Road
- Redevelopment of Yashwant Place Commercial Complex
- Bus terminus-cum-commercial complex near Shivaji Stadium

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE millenniumpost
NEW DELHI | FRIDAY, 20 MAY, 2022 --DATED----------

Govt agencies say will comply with HC stay on felling trees

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: With the High Court here ordering a stay on any further felling of trees in Delhi till June 2, several government agencies in the national Capital stated that it will only have a "minor" impact on their ongoing projects.

Many key infrastructure projects are being carried out by different agencies and departments such as National Building Construction Corporation (NBCC), Central Public Works Department (CPWD), PWD, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) and Delhi Development Authority (DDA) among others.

After the court order, the forest department said they will ensure its compliance.

"We will ensure the court order is adhered to. We will send the court order to all the agencies and project proponents for strict implementation," a senior forest official said.

The key ongoing infrastructure projects in the city include the Central Vista project, construction of Barapullah phase-3 elevated corridor, tunnel beneath Pragati Maidan, redevelopment of GPRA colonies in Sarojini Nagar and Netaji Nagar and the construction of three new metro lines under phase four.

A PWD official requesting anonymity said that the stay on tree felling will have only a "minor impact".

"The order will be followed which may lead to only a minor impact on our projects," the official said. The Engineer-in-Chief of the PWD, Anant Kumar, said that any major impact is unlikely.

"Our construction projects are already in an advanced stage so any major impact is unlikely there. The permissions for tree felling or tree transplantation are generally taken and executed at the start of the projects. We will follow the court order," Kumar said.

An official of the CPWD, which is executing the Central Vista project, said that the department will follow all the prescribed rules.

"CPWD does not do tree cutting while executing its projects in most cases.

"Under the Central Vista redevelopment project, no tree is being cut by us. We usually transplant trees and follow all laid down rules," a senior CPWD official said.

The redevelopment of the Central Vista, the nation's power corridor, envisages a new parliament building, common central secretariat, revamping of the 3-km Rajpath from the Rashtrapati Bhavan to India Gate, a new office and residence of the prime minister, and a new vice-president enclave.

The DMRC and DDA refused to comment on the stay. Sources said that the legal department of DDA will examine the high court order.